

## छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर जी.एस.टी परषिद की बैठक में ट्रबि्यूनल में दो न्यायकि सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य रखे जाने पर बनी आम सहमतति

### चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2023 को वतित एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री नरिमला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजति जी.एस.टी परषिद की बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से ट्रबि्यूनल में दो न्यायकि सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य (एक राज्य और एक केंद्र) रखे जाने के प्रस्ताव पर परषिद में आम सहमतति बनी ।

### प्रमुख बदि

- इससे सहकारी संघवाद का समुचति ध्यान रखते हुए राज्यों को भी उचति प्रतनिधित्व प्राप्त हो सकेगा । राज्यों को उनके भौगोलकि एवं अन्य प्रस्थितियों के आधार पर ट्रबि्यूनल के बेंच की संख्या का निर्धारण का अधिकार भी होगा ।
- वदिति है कि जी.एस.टी. परषिद की 49वीं बैठक नई दल्लिी स्थति वजिज्ञान भवन में आयोजति हुई । बैठक में केंद्रीय वतित राज्य मंत्री पंकज चौधरी व अन्य राज्यों के वतितमंत्री, अधिकारीगण तथा छत्तीसगढ़ आयुक्त, वाणजियकि कर भीम सहि भी शामिल हुए ।
- यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के वाणजियकि कर मंत्री टी.एस. सहिदेव द्वारा रखा गया था । छत्तीसगढ़ द्वारा कषतपूरति की राशि शीघ्र प्रदान करने की मांग की गई । केंद्र शासन द्वारा 505 करोड़ रुपए कषतपूरति राशि तत्काल दये जाने का नरिणय लया गया ।
- बैठक में मुख्य मुद्दा जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण (ट्रबि्यूनल) का रहा । मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मद्रास बार एसोसिएशन के प्रकरण में टीएनजीएसटी के ट्रबि्यूनल संबंधी प्रावधान को अवैधानकि घोषति करने के पश्चात् अधिकरण संबंधी प्रावधान पर पुनर्वचार हेतु मंत्री समूह का गठन कया गया था । इस मंत्री समूह का प्रतविदन बैठक में प्रस्तुत कया गया ।
- तेंदूपत्ता पर जी.एस.टी. की दर को शून्य करने के उड़ीसा के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ने यथास्थति बनाए रखने का समर्थन कया । पूर्व में परषिद की 22वीं एवं 37वीं बैठक में दर अपरविरतनीय रखने के नरिणय एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अभमित के आधार पर यथास्थति बनाए रखने का नरिणय लया गया ।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण तेंदूपत्ता संग्राहकों को देश भर में सर्वाधिक लाभ प्रदान कया जाता है । अधिकितम लाभ अंतरति कये जाने से कर का भार संग्राहको को वहन नही करना पड़ता है साथ ही तेंदूपत्ता पर आरसीएम (रविरस चार्ज) होने से भी कर का भार शासन द्वारा वहन कया जाता है ।
- भारतीय कसिान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कर का भुगतान करने के पश्चात् खरीदे गए खाद, कृषियंत्र आदि पर ऐसे आगत कर कसिानों को भी देने (जैसा कि अन्य नरिमाताओं को दया जाता है) का प्रस्ताव दया गया ।
- गौरतलब है कि आगत कर की पात्रता, पंजीयन एवं कर योग्य वकिरय होने पर ही होती है । पंजीयन एवं कर योग्य वकिरय नही होने पर कसिानों की आगत कर की पात्रता नही है । अतः छत्तीसगढ़ की ओर से इस प्रस्ताव को रूपांतरति कर कसिानों द्वारा उपयोग कये जा रहे समस्त सामग्रियों को जी.एस.टी. से सरकार मुक्त रखने का प्रस्ताव परषिद के समकष रखा गया, जसिे वचिरार्थ फटिमेंट कमटी को प्रेषति कये जाने हेतु अनुशंसा की गई ।